



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 2019/आश्विन 11, 1941
No. 316]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 2019/ASVINA 11, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2019

एसएसआर सं. 07/2019

विषय : चीन जन.गण., मलेशिया और कोरिया गणराज्य के से स्टेनलैस स्टील-304 ग्रेड के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

फा. सं. 7/16/2019—डी जी टी आर.—समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण एवं क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे यहां इसके बाद नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/30/2013- डी जी ए डी दिनांक 9.3.2015 द्वारा चीन जन.गण., मलेशिया और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टेनलैस स्टील-304 ग्रेड के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों (जिन्हें आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । शुल्क दिनांक को 5.6.2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 28/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा लागू किया गया था ।

2. और यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9 क (5) के अनुसार यदि पाटनरोधी शुल्क को पहले न हटाया जाए तो वह उसे लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष से समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जाते हैं और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है ।

3. और यतः जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लि. और जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने संयुक्त रूप से अधिनियम और नियमावली के अनुसार चीन जन.गण., मलेशिया, और कोरिया गणराज्य से स्टेनलैस स्टील-304 ग्रेड के हॉट रोलड फ्लैट उत्पादों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की है।

4. और यतः तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्राधिकारी की राय है कि चीन जन.गण., मलेशिया, और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

क. विचाराधीन उत्पाद

5. याचिका में विचाराधीन उत्पादन मूल जांच के समान ही है जिसे अंतिम जांच परिणाम में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

“हॉट रोलड ऑस्टेनैटिक स्टेनलैस स्टील फ्लैट उत्पाद चाहे प्लेटों, शीटों या क्वायलों में आयताकार हों (हॉट रोलड एनील्ड या पिकल्ड या ब्लैक); तथा 304 या 304एच या 304एल या 304एन या 304एल एन या ईएन 1.4311, ईएन 1.4301, ईएन 1.4307 या एक्स 5 सीआरएनआई 1810 या एक्स 04सीआर 19एनआई 9, या किसी अन्य मानक जैसे यूएनएस, डीआईएन, जेआईएस, बीआईएच, ईएन आदि के समतुल्य हों आदि, चाहे नं.1 या ब्लैक फिनिश हो अथवा नहीं, चाहे प्राइम या नॉन प्राइम गुणवत्ता के हो, चाहे मिल एज या ट्रिम एज के साथ एज की स्थिति में हो अथवा नहीं, जिनकी मोटाई 1.2 मिमि. से 10.5 मिमि., क्वायल में हो और प्लेटों या शीटों में 3 मिमि. से 105 मिमि. तक, तथा 1650 मिमि. (चौड़ाई सहनशीलता + मिल एज के लिए 20 मिमि. और + ट्रिम एज के लिए 5 मिमि.) की समस्त चौड़ाइयों में हो।”

6. विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय उप-शीर्ष 7219 तथा 7220 के तहत वर्गीकृत है।

7. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद मूलतः की गई जांच में यथापरिभाषित के समान रहेगा। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान कोई खास गतिविधियां नहीं हुई हैं।

ख. समान वस्तु

8. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

9. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।

10. याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

11. निर्णायक समीक्षा के शुरुआत हेतु यह याचिका जिंदल स्टेनलैस (हिसार) लिमिटेड और जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप में दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं के अलावा देश में विचाराधीन उत्पाद के दो अन्य उत्पादक अर्थात् शाह अलॉय तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैं।

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह भारत में किसी आयातक या संबद्ध देशों में किसी निर्यातक से संबंधित नहीं है और न ही उन्होंने संबद्ध वस्तु का आयात किया है।

13. रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आवेदक का उत्पादक समान वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है इसलिए याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंड को पूरा करते हैं।

घ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

14. घरेलू उद्योग द्वारा पाटन और क्षति के जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हुए प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं ताकि समीक्षा की जा सके कि क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा की जा सके और इस बात की जांच की जा सके कि क्या लागू शुल्क को हटाये जाने से पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ड. संबद्ध देश

15. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल संबद्ध देश चीन जन.गण., मलेशिया और कोरिया गणराज्य हैं।

च. जांच की अवधि

छ. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2018 – मार्च, 2019 (12 महीने) है और क्षति जांच की अवधि में 2015-16, 2016-17, 2017-2018 और जांच अवधि शामिल होगी।

ज. प्रक्रिया

16. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों व प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

निर्दिष्ट प्राधिकारी

व्यापार उपचार महानिदेशालय

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

18. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत कोई अनुरोध ऊपर दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षों को उसे उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

झ. समय-सीमा

19. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की सूचना देने वाले पत्र जारी करने की तारीख से दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित 40 (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार तो प्राधिकारी, रिकॉर्ड में के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज "उपलब्ध तथ्यों" कर सकते हैं।

ट. **गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

20. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए और उनकी साफ्ट प्रतियां होनी चाहिए।

21. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

22. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

23. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/ रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

24. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

25. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ठ. **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

26. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

27. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd October, 2019

SSR No. 07/2019**Sub. : Initiation of Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel- 304 grade from China PR, Malaysia and Korea RP.**

F. No. 7/16/2019-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty vide notification No. 14/30/2013-DGAD dated 09.03.2015 on imports of “Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel- 304 grade”, (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from China PR, Malaysia and Korea RP (hereinafter collectively referred to as the subject countries). The same were imposed vide customs notification no. 28/2015-Customs (ADD) dated 05.06.2015.

2. Whereas, in terms of Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995, the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation of dumping and injury.

3. And whereas, Jindal Stainless (Hisar) Limited and Jindal Stainless Limited (hereinafter referred to as ‘Petitioners’) jointly have filed a review petition for continued imposition of Anti-dumping duty on imports of Hot Rolled Flat Products of Stainless Steel-304 grade from China PR, Malaysia and Korea RP, in accordance with the Act and Rules.

4. And whereas, based on the facts and data, the Authority is of the opinion that there is a need to review for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR, Malaysia and Korea RP.

A. Product under Consideration

5. The product under consideration in the petition is the same as the original investigations, which was defined as follows in the final findings-

“Hot Rolled austenitic stainless steel flat products; whether or not plates, sheets or coils (hot rolled Annealed and pickled or Black) of rectangular shape; of grade either 304 or 304H or 304L or 304N or 304LN or EN 1.4311, EN 1.4301, EN1.4307 or X5CRNI1810 or X04Cr19Ni9, or equivalents thereof in any other standards such as UNS, DIN, JIS, BIS, EN, etc.; whether or not with number one or Black finish; whether or not of quality prime or non-prime; whether or not of edge condition with mill edge or trim edge; of thickness in the range of 1.2mm to 10.5mm in Coils and 3mm to 105mm in Plates & Sheets; of all widths up to 1650mm(width tolerance of + 20mm for mill edge and + 5mm for trim edge)”

6. The product under consideration is classified under chapter sub-heading 7219 and 7220 of Customs Tariff Act, 1975.

7. Present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the originally conducted investigation. Further, no significant developments have taken place over the period.

B. Like Article

8. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

9. Petitioners have claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject countries. Subject goods produced by the petitioners and imported from the subject countries are comparable in terms of physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
10. Subject goods produced by the petitioner companies are being treated as 'like article' to that being imported from the subject countries for the purpose of the present review investigation.

C. Domestic Industry

11. The petition for initiation of sunset review is being jointly filed by Jindal Stainless (Hisar) Limited and Jindal Stainless Limited. There are two more producers of the product under consideration in the country, other than the petitioners, i.e., Shah Alloys and Steel Authority of India Ltd.
12. Petitioners have claimed that they are not related to any importer in India or exporter in the subject countries nor have they imported the subject goods.
13. As per the evidence available on record, the production of the applicant accounts for a major proportion in the total domestic production of the like article. The petitioners thus constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti-dumping Rules and satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

D. Initiation of Sunset Review Investigation

14. Having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury, in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

E. Subject Countries

15. The subject countries involved in the present sunset review investigation are China PR, Malaysia and Korea RP.

F. Period of investigation

- G. The period of investigation (POI) for the present investigation is April 2018-March 2019 (12 months) and the injury investigation period is from 2015–2016, 2016–2017, 2017-2018 and the POI.

H. Procedure

16. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

I. Submission of Information

17. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through its embassy in India, the known importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Department of Commerce
Ministry of Commerce and Industry
4th Floor, Jeevan Tara Building
5, Parliament Street, New Delhi – 110001

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out above. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same to be made available to the other parties.

J. Time Limit

19. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise of the anti-dumping measures within 40 days from the date of issue of letter by the authority intimating initiation of the investigation. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

K. Submission of Information on Confidential Basis

20. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page and accompanied with soft copies.
21. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and two (02) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.
22. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.
23. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
24. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
25. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

L. Inspection of Public File

26. In terms of rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by other interested parties.

M. Non-Cooperation

27. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority